

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे) एवं III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

02 जनवरी, 2020

“बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने भी लैंगिक समानता हासिल करने में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।”

सोमवार को नीति आयोग का सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक, 2019 जारी किया गया, जिसमें कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं मिला है। दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में शामिल हैं, जबकि उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्वी राज्य 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ गए हैं।

उत्तर प्रदेश जैसे कमजोर प्रदर्शनकारी राज्य ने सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा को

TOP 12, THE STATES

Kerala	70
Himachal	69
Andhra	67
Tamil Nadu	67
Telangana	67
Karnataka	66
Goa	65
Sikkim	65
Gujarat	64
Maharashtra	64
Uttarakhand	64
Punjab	62

BOTTOM 5, THE STATES

Bihar	50
Jharkhand	53
Arunachal	53
Meghalaya	54
UP, Assam	55

TOP 5, THE UTs

Chandigarh	70
Puducherry	66
Dadra & NH	63
Lakshadweep	63
Delhi, A&N	61
Islands, Daman & Diu	

अपनाने और स्वच्छता में सुधार करने के मुद्दे पर। लेकिन यह 'गरीबी उन्मूलन' और 'अच्छा स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन' या 'उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचे' जैसे बुनियादी आजीविका लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे हो गया है।

यह राज्य शासन और प्रशासनिक संरचनाओं और कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में भिन्नताओं को इंगित करता है। केरल और तमिलनाडु के नेतृत्व में दक्षिण ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और भूखमरी कम करने जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक संस्थानों को उन्मुख करने में बेहतर कार्य किया है।

साथ ही इन्होंने एक शासन संरचना के साथ इन मोर्चों पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। यह सिलसिला उत्तरी राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में ठीक उल्टा है, जहाँ शासन संरचना में बहुत अधिक अंतर नहीं होने के बावजूद परिणाम अपेक्षाकृत खराब बने हुए हैं।

पहेली का स्पष्ट उत्तर ऐतिहासिक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की उपस्थिति हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सत्ता में कुलीनों का अधिक प्रसार हुआ है और जिन्होंने विशेष रूप से दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में कल्याण से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया है। फिर भी इन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्य तक पहुँचने एवं विश्व और अन्य विकासशील देशों दोनों के जीवन स्तर को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

पश्चिमी राज्य, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र, आर्थिक विकास और उद्योग में बेहतर हैं, जो एक विविध अर्थव्यवस्था, उच्च रोजगार अनुपात, कुशल श्रम और बेहतर उद्यमशीलता संस्कृति का संकेत देते हैं।

GOAL BY GOAL, THE STATES

Sustainable development goal	Top score	2nd place	Bottom rank
SDG 1: No poverty	Tamil Nadu (72)	Tripura (70)	Jharkhand (28)
SDG 2: Zero hunger	Goa (76)	Mizoram (75)	Jharkhand (22)
SDG 3: Good health	Kerala (82)	Andhra (76)	Nagaland (29)
SDG 4: Quality education	Himachal (81)	Kerala (74)	Bihar (19)
SDG 5: Gender equality	Himachal (52)	Kerala (51)	Telangana (26)
SDG 6: Clean water & sanitation	Andhra (96)	UP (94)	Tripura (69)
SDG 7: Affordable & clean energy	Sikkim (97)	Goa (95)	Odisha (50)
SDG 8: Decent work & economic growth	Telangan (82)	Andhra (78)	Manipur (27)
SDG 9: Industry, innovation, infrastructure	Gujarat (88)	Kerala (88)	Mizoram (8)
SDG 10: Reduced inequalities	Telangana (94)	Manipur (81)	Goa (19)
SDG 11: Sustainable cities & communities	Goa (79)	Himachal (79)	Meghalaya (22)
SDG 12: Sustainable consumption & production	Nagaland (100)	Tripura (92)	Rajasthan (30)
SDG 13: Climate action	Karnataka (71)	Andhra (70)	Jharkhand (27)
SDG 14: Marine ecosystems	Coastal states only, not counted in overall SDG		
SDG 15: Life & land	Manipur (100)	Sikkim (100)	Haryana (40)
SDG 16: Peace, justice & strong institutions	Andhra (86)	Gujarat (86)	Assam (52)

भारत में सबसे बड़ी समस्या लिंग-समानता हासिल करने से संबंधित है, जहाँ हिमाचल प्रदेश, केरल और जम्मू-कश्मीर जैसे औसत दर्जे वाले प्रदर्शनकारी राज्यों को छोड़ दे, तो देश के बाकी हिस्सों में इस समस्या को बड़ी संख्या में देखा जा सकता है।

कम लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर 896 महिलाएँ), कमजोर श्रम शक्ति की भागीदारी और प्रबंधनीय पदों पर उपस्थिति (केवल 17.5% और 30%, रिपोर्ट के अनुसार), श्रम की अनौपचारिकता का उच्च स्तर, लिंग-आधारित वेतन में अंतर (जहाँ महिलाएँ नियमित वेतनभोगी रोजगार में पुरुषों द्वारा अर्जित मजदूरी का 78% ही कमा पाती हैं), शासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी (संसद में 14.4%, लेकिन स्थानीय सरकार में 44.4%) इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ उच्च अपराध दर राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संकेतकों में से एक है जिन्होंने इसमें योगदान दिया है।

लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए राज्यों को बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है उअर इसमें समय भी लगेगा, लेकिन संसदीय आरक्षणों के माध्यम से शासन में

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे तात्कालिक कदम इनके द्वारा सामना किए जा रहे कई मुद्दों को दूर करने में सफल साबित होगा।

High-performing Union Territories

Sustainable development goal	High UT scores
SDG 4: Quality education	Chandigarh (80)
SDG 5: Gender equality	J&K (53), Ladakh (53)
SDG 6: Clean water & sanitation	Chandigarh (100), Daman & Diu (96)
SDG 7: Affordable & clean energy	Puducherry (97), Delhi (96)
SDG 9: Industry, innovation, infrastructure	Dadra & NH (100), Daman & Diu (100), Delhi (100)
SDG 10: Reduced inequalities	A & N Islands (94), Lakshadweep (93), Puducherry (92)
SDG 11: Sustainable cities & communities	Chandigarh (83)
SDG 13: Climate action	Lakshadweep (100), A & N Islands (72)
SDG 15: Life & land	Dadra & NH 100, Lakshadweep 100
SDG 16: Peace, justice & strong institutions	Puducherry 96, Chandigarh 89

नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी) की दिशा में राज्यों की स्थिति पर हाल ही में समग्र रिपोर्ट जारी की। इसमें केरल एक बार फिर सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने में सबसे आगे रहा।
- इस सूचकांक में भारत का समग्र अंक जहाँ 2018 में 57 था, 2019 में इसमें तीन अंकों की वृद्धि हुई है और यह सूचकांक 60 पर पहुँच गया है।
- नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया सूचकांक-2019 में बताया कि यूपी सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।
- एसडीजी के तहत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है।

मुख्य बिंदु

- मुख्य रूप से-जल एवं स्वच्छता, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन एसडीजी स्कोर कार्ड को गहराई से देखने से पता चलता है कि कम से कम छह एसडीजी लक्ष्यों पर देश की प्रगति में गिरावट आई है।
- ये हैं - एसडीजी 1 (गरीबी से मुक्ति), एसडीजी 2 (शून्य से मुक्ति), एसडीजी 8 (निर्णय कार्य और आर्थिक विकास), एसडीजी 10 (असमानता से मुक्ति), एसडीजी 15 (जमीन पर जीवन) और एसडीजी 16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ)।
- नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रिपोर्ट में कहा, "2018 में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 13 लक्ष्यों को शामिल किया गया था, लेकिन 2019 में सभी 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है।

सूचकांक के अनुसार

- कुल सूचकांक में सुधार के बावजूद भूख को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य के मामले में भारत की प्रगति सबसे खराब रही है। 2018 में देश का कुल स्कोर 48 अंक था, जो 2019 में गिरकर 38 अंक हो गया है।
- अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भी भारत के इस पहलू पर खराब प्रदर्शन का उल्लेख किया गया था। इस सूचकांक में 117 प्रमुख देशों में भारत का स्थान 102वां था।
- नीति आयोग का सूचकांक बताता है कि 25 राज्य भूख एवं कुपोषण के लक्ष्य को हासिल करने में विफल साबित हो रहे हैं।
- 100 में से 22 अंकों के साथ झारखंड ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश (24 अंक) और बिहार (26 अंक) भी

प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं। लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने वाले अन्य राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, मेघालय, उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं।

□ भले ही गोवा ने 76 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, लेकिन उसका कुल स्कोर भी 4 अंक हो गया। वास्तव में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से 5 ने इस साल भी अपने समग्र अंकों में गिरावट दर्ज की है। ये छह राज्य हैं- मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर।

□ इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य के तहत देश में 5 साल से कम आयु वर्ग के कमजोर बच्चों की संख्या 2.5 फीसदी होनी चाहिए, लेकिन भारत में उनकी संख्या 34.7 फीसदी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से देश को खाद्यान्न उत्पादन में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है और यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट कहती है कि गरीबी को समाप्त करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देश गरीबी खत्म करने के लक्ष्य से 4 अंक नीचे 54 से 50 पर फिसल गया है। 22 राज्य लक्ष्य के मुताबिक अपनी गरीबी कम नहीं कर पाए हैं। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर राष्ट्र भी फिसल गया है। गोवा 100 में से सिर्फ 19 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। वह पिछले साल के मुकाबले 31 अंक नीचे पहुँच गया है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए महत्वकांक्षी वैश्विक विकास लक्ष्य हैं जो सार्वभौमिक जन कल्याण से संबंधित हैं।
- ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संबंधित हैं तथा इनमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य तय किये गये हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच

सुनिश्चित करना।

8. सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
9. लचीले बुनियादी ढाँचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा।
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।

14. स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
16. सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
17. सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. नीति आयोग द्वारा जारी “सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019” से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस सूचकांक में 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया था।
2. इस सूचकांक में उत्तर-मध्य भारत के दस राज्य शीर्ष में बने रहे।
3. इसमें सबसे ज्यादा सुधार करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- | | |
|------------|------------|
| (a) 1 और 2 | (b) केवल 1 |
| (c) 1 और 3 | (d) केवल 3 |

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of the First Sustainable Development Goals Index 2019 released by NITI Aayog:

1. 17 targets were included in this index
2. The states of North-Central India remained in the top ten in this index.
3. The most improving state in it was Uttar Pradesh

Which of the above statements is/are correct?

- | | |
|-------------|------------|
| (a) 1 and 2 | (b) Only 1 |
| (c) 1 and 3 | (d) Only 2 |

नोट : 30 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: ‘सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एक देश विशेष के सर्वांगीण विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’ हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

The Sustainable Development Goals Index shows its commitment to the all-round development of a particular country. Review the performance of states in the Sustainable Development Goals Index recently released by NITI Aayog. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।